

अनुदान संख्या 46 – भारी उद्योग विभाग
GRANT No. 46 – DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	927,85,00		
			1113,57,00	1050,93,01
पूरक	Supplementary	185,72,00		-62,63,99
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			61,96,20
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	67,42,00		
			177,49,00	127,04,99
पूरक	Supplementary	110,07,00		-50,44,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			19,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹6263.99 लाख) जुलाई, 2021, दिसंबर 2021 तथा मार्च, 2022 में प्राप्त किए गए ₹18572.00 लाख के पूरक अनुदान का 34 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 6 प्रतिशत थीं।
1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹6263.99 lakhs) constituted 34 percent of the supplementary grant of ₹18572.00 lakhs obtained in July, 2021, December, 2021 and March, 2022 and 6 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआः—

Savings/excess occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत -
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	4109.00			
			3218.30	3202.83	-15.47
पु.	R.	-890.70			
मुख्य शीर्ष "2852" उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	88676.00			
पू.	S.	18572.00	101942.50	101890.18	-52.32
पु.	R.	-5305.50			

(I) ₹400.00 लाख का पूरक प्रावधान मुख्य शीर्ष "2852" – "सामान्य" – सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता – ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास" – के अंतर्गत एक मामले में – कोविड-19 महामारी के कारण कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – भारी उद्योग विभाग" के अंतर्गत – ₹906.17 लाख की बचत (₹4109.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने तथा कोविड-19 महामारी के कारण यात्रा खर्चों, अन्य प्रशासनिक खर्चों, विज्ञापन तथा प्रचार, लघु कार्यों और व्यावसायिक सेवाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(I) Supplementary provision of ₹400.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "2852" - "General – Assistance to Public Sector and other Undertakings – Development of Automobile Industry" – due to non-receipt of proposals from implementing agencies owing to COVID-19 pandemic.

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Heavy Industry" - saving of ₹906.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4109.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, requirement of less funds towards travel expenses, other administrative expenses, advertisement and publicity, minor works and professional services owing to COVID-19 pandemic.

(III) मुख्य शीर्ष "2852" - "सामान्य - अन्य व्यय - पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का विकास" के अंतर्गत - ₹6910.80 लाख की बचत (₹11309.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 महामारी के कारण कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1956.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "2852" - "सामान्य - अन्य व्यय - ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास" के अंतर्गत ₹18571.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹1954.98 लाख था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹5044.01 लाख) जुलाई, 2021 तथा दिसंबर, 2021 में प्राप्त किए गए ₹11007.00 लाख के पूरक अनुदान का 46 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 28 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ:-

(III) Under Major Head "2852" - "General - Other Expenditure - Development of Capital Goods Sector"- saving of ₹6910.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11309.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from implementing agencies owing to COVID-19 pandemic.

2. The above savings were partly (₹1956.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹18571.00 lakhs under Major Head "2852" - "General - Other Expenditure - Development of Automobile Industry". Actual excess, however, was ₹1954.98 lakhs.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹5044.01 lakhs) constituted 46 percent of the supplementary grant of ₹11007.00 lakhs obtained in July, 2021 and December, 2021 and 28 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
मुख्य शीर्ष "6858"	Major Head "6858"			
इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए कर्ज	Loans for Engineering Industries			
मू.	O.	6730.00		
पू.	S.	1.00	6723.00	1700.00
पु.	R.	-8.00		-5023.00

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

(I) ₹6740.00 लाख का प्रावधान उन्नीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹6722.00 लाख अकेले - "अन्य इंजीनियरिंग उद्योग - अन्य ऋण - राष्ट्रीय ऑटोमोटिव टेस्टिंग और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजनाएं" के अंतर्गत - इस स्कीम का विस्तार न किए जाने का निर्णय लिए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹6740.00 lakhs remained wholly unutilized under nineteen heads; of these ₹6722.00 lakhs alone accounted for under "Other Engineering Industries - Other Loans - Loans to National Automotive Testing and R&D Infrastructure Projects" - due to decision taken for non-extension of the scheme.

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1700.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि "अन्य इंजिनियरिंग उद्योग – अन्य ऋण – ऑटोमोबाईल्स तथा सम्बद्ध उद्योग के लिए विकास परिषद" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹1699.00 लाख था।

4. The above savings were partly (₹1700.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under "Other Engineering Industries – Other Loans –Development Council for Automobiles and Allied Industries". Actual excess, however, was ₹1699.00 lakhs.
